

ग्रामीण विकास में जनसंचार माध्यमों की भूमिका-एक समाजशास्त्रीय अध्ययन (सीधी जिले के कुसमी तहसील के विशेष संदर्भ में)

Research Scholar

Priyanka Gautam

Enrollment No. 22ASSH1SL06002

Supervisor

Dr. Manish Mishra

Deptt. of Sociology

SAM Global University, Raisen

(Madhya Pradesh)-464551

सारांश (Abstract)

प्रस्तुत शोध पत्र मध्य प्रदेश के सीधी जिले की कुसमी तहसील में ग्रामीण विकास की प्रक्रिया में जनसंचार माध्यमों की भूमिका का समाजशास्त्रीय विश्लेषण प्रस्तुत करता है। अध्ययन प्राथमिक तथा द्वितीयक, दोनों प्रकार के स्रोतों पर आधारित है। प्राथमिक समकों का संकलन कुसमी तहसील से स्तरीकृत यादृच्छिक प्रतिचयन पद्धति के माध्यम से चयनित 100 ग्रामीण महिलाओं से संरचित साक्षात्कार-अनुसूची के माध्यम से किया गया, जबकि द्वितीयक समंक जनगणना, जिला सांख्यिकी पुस्तिका तथा सम्बद्ध शोध-साहित्य से प्राप्त किए गए। अध्ययन से यह स्पष्ट हुआ कि मोबाइल फोन (82 प्रतिशत) तथा दूरदर्शन (50 प्रतिशत) कुसमी तहसील में सर्वाधिक व्यापक जनसंचार साधन हैं, तथा जनसंचार माध्यम (42 प्रतिशत) ग्रामीण विकास योजनाओं की जानकारी का सर्वाधिक सामान्य स्रोत बनकर उभरे हैं, जो सरकारी कर्मचारियों (25 प्रतिशत) तथा पारिवारिक/सामाजिक स्रोतों (20 प्रतिशत) से भी आगे हैं। माध्यम-उपयोग स्तर तथा ग्रामीण विकास योजनाओं की जागरूकता के मध्य सांख्यिकीय रूप से सार्थक सकारात्मक सम्बन्ध भी पाया गया। अध्ययन के निष्कर्ष यह रेखांकित करते हैं कि जनसंचार माध्यम कुसमी जैसी दुर्गम, जनजातीय-बाहुल्य तहसील में ग्रामीण विकास की सूचनात्मक बुनियाद को सुदृढ़ करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, यद्यपि अवसंरचनात्मक तथा सामाजिक-सांस्कृतिक बाधाएँ अभी भी विद्यमान हैं।

मुख्य शब्द (Keywords)

ग्रामीण विकास, जनसंचार माध्यम, कुसमी तहसील, सीधी जिला, ग्रामीण महिलाएँ, सूचना-पहुँच, पंचायती राज, विकास-सम्प्रेषण।

प्रस्तावना

स्वतंत्रता-प्राप्ति के पश्चात् भारत में ग्रामीण विकास सरकारी नीति-निर्माण का एक केन्द्रीय सरोकार रहा है, क्योंकि देश की बहुसंख्य जनसंख्या आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। ग्रामीण विकास की प्रक्रिया में कृषि-उत्पादकता में वृद्धि, स्वास्थ्य तथा शिक्षा-सुविधाओं का विस्तार, अवसंरचनात्मक सुधार तथा सामाजिक-आर्थिक असमानता में कमी जैसे बहुआयामी लक्ष्य सम्मिलित हैं। इस सम्पूर्ण प्रक्रिया में जनसंचार माध्यमों-रेडियो, दूरदर्शन, समाचार-पत्र तथा वर्तमान में मोबाइल फोन-की भूमिका को समाजशास्त्रीय साहित्य में बार-बार महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि ये माध्यम सरकारी योजनाओं, कृषि-नवाचार तथा स्वास्थ्य-सम्बन्धी सूचना को ग्रामीण जनसंख्या तक पहुँचाने का एक प्रमुख वाहक हैं (श्राम, 1964; रोजर्स, 2003)।

मध्य प्रदेश के सीधी जिले की कुसमी तहसील, जो जिले की सर्वाधिक दुर्गम तथा वनाच्छादित तहसीलों में से एक मानी जाती है, तथा जहाँ बैगा, कोल एवं गोंड जनजातियों की सघन उपस्थिति है, ग्रामीण विकास की चुनौतियों तथा जनसंचार माध्यमों की सम्भावित भूमिका, दोनों के अध्ययन हेतु एक विशेष रूप से उपयुक्त क्षेत्र प्रस्तुत करती है। यह तहसील राज्य तथा राष्ट्रीय औसत की तुलना में निम्न साक्षरता-दर, सीमित अवसंरचना तथा उच्च निर्धनता-दर जैसी विशेषताओं से चिन्हित है (मध्य प्रदेश मानव विकास प्रतिवेदन)।

प्रस्तुत शोध पत्र इसी सन्दर्भ में यह अन्वेषित करने का प्रयास करता है कि कुसमी तहसील की ग्रामीण महिलाओं की जनसंचार माध्यमों तक वर्तमान पहुँच क्या है, तथा ग्रामीण विकास से सम्बन्धित सूचना के प्रसार में ये माध्यम किस सीमा तक तथा किस रूप में योगदान दे रहे हैं। अध्ययन प्राथमिक क्षेत्र-सर्वेक्षण तथा द्वितीयक स्रोतों, दोनों के समन्वित उपयोग पर आधारित है, जिससे स्थानीय अनुभवजन्य साक्ष्य को व्यापक सांख्यिकीय तथा सैद्धांतिक सन्दर्भ में स्थापित किया जा सके।

शोध पत्र का उद्देश्य

प्रस्तुत शोध पत्र के निम्नलिखित प्रमुख उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं :

1. कुसमी तहसील की सामाजिक-आर्थिक तथा अवसंरचनात्मक पृष्ठभूमि का अध्ययन करना।
2. कुसमी तहसील की ग्रामीण महिलाओं की जनसंचार माध्यमों तक पहुँच एवं उपयोग-प्रतिमान का विश्लेषण करना।
3. ग्रामीण विकास योजनाओं तथा कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्ति में जनसंचार माध्यमों के सापेक्षिक योगदान का परीक्षण करना।
4. माध्यम-उपयोग स्तर तथा ग्रामीण विकास-सम्बन्धी जागरूकता के मध्य सम्बन्ध का सांख्यिकीय विश्लेषण करना।
5. अनुभवजन्य निष्कर्षों के आधार पर कुसमी तहसील में ग्रामीण विकास हेतु जनसंचार माध्यमों के प्रभावी उपयोग सम्बन्धी सुझाव प्रस्तुत करना।

महत्व

प्रस्तुत अध्ययन का महत्व अनेक दृष्टिकोणों से स्पष्ट होता है। सैद्धांतिक दृष्टि से, यह अध्ययन ग्रामीण विकास तथा जनसंचार माध्यमों के मध्य सम्बन्ध पर उपलब्ध साहित्य को कुसमी जैसी अपेक्षाकृत उपेक्षित, दुर्गम तथा जनजातीय-बाहुल्य तहसील के विशिष्ट सन्दर्भ में परीक्षित करते हुए एक क्षेत्रीय अनुभवजन्य योगदान प्रस्तुत करता है, जो सीधी जिले तथा व्यापक बघेलखण्ड क्षेत्र पर केन्द्रित समाजशास्त्रीय साहित्य में विद्यमान एक रिक्तता को आंशिक रूप से भरने का प्रयास करता है।

व्यावहारिक दृष्टि से, अध्ययन के निष्कर्ष पंचायती राज संस्थाओं, ग्रामीण विकास विभाग, कृषि-विस्तार अभिकरणों तथा स्थानीय अशासकीय संगठनों को कुसमी तहसील की ग्रामीण महिलाओं तक विकासात्मक सूचना प्रभावी ढंग से पहुँचाने हेतु साक्ष्य-आधारित दिशा-निर्देश प्रदान करते हैं। डिजिटल इंडिया, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण तथा ई-गवर्नेंस

जैसी पहलों के विस्तार के इस युग में, यह समझना अत्यन्त प्रासंगिक हो गया है कि दुर्गम, जनजातीय-बाहुल्य तहसीलों की ग्रामीण महिलाएँ इस सूचना-क्रान्ति से किस सीमा तक लाभान्वित हो रही हैं।

शोध प्रविधि

शोध अभिकल्प - प्रस्तुत अध्ययन वर्णनात्मक-सह-विश्लेषणात्मक (descriptive-cum-analytical) शोध अभिकल्प पर आधारित है, जिसमें प्राथमिक तथा द्वितीयक, दोनों प्रकार के समकों का समन्वित उपयोग किया गया है।

प्राथमिक समंक - प्राथमिक समकों का संकलन कुसमी तहसील के विभिन्न ग्रामों से स्तरीकृत यादृच्छिक प्रतिचयन (stratified random sampling) पद्धति के माध्यम से चयनित 100 ग्रामीण महिलाओं से संरचित साक्षात्कार-अनुसूची के माध्यम से किया गया। अनुसूची में सामान्य पहचान, सामाजिक-आर्थिक स्थिति, जनसंचार माध्यमों तक पहुँच एवं उपयोग, तथा ग्रामीण विकास योजनाओं की जागरूकता से सम्बन्धित प्रश्न सम्मिलित थे। साक्षात्कार स्थानीय बोली में सम्पन्न किए गए, तथा प्रत्येक उत्तरदाता से सूचित सहमति प्राप्त कर पूर्ण गोपनीयता सुनिश्चित की गई।

द्वितीयक समंक - द्वितीयक समकों हेतु भारत की जनगणना, मध्य प्रदेश मानव विकास प्रतिवेदन, जिला सांख्यिकी पुस्तिका-सीधी, जनजातीय अनुसंधान एवं विकास संस्थान भोपाल के प्रतिवेदन, तथा ग्रामीण विकास एवं जनसंचार माध्यमों पर उपलब्ध प्रकाशित शोध-साहित्य का उपयोग किया गया, जिसका उपयोग मुख्यतः अध्ययन-क्षेत्र के परिचय, सैद्धांतिक पृष्ठभूमि तथा प्राथमिक निष्कर्षों के व्यापक सन्दर्भीकरण हेतु किया गया।

समंक-विश्लेषण - संकलित प्राथमिक आँकड़ों का विश्लेषण वर्णनात्मक सांख्यिकी (बारम्बारता, प्रतिशत) तथा क्रॉस-सारणीयन (cross-tabulation) के माध्यम से किया गया, जिसे उपयुक्त सारणियों में प्रस्तुत तथा विश्लेषित किया गया है।

अध्ययन क्षेत्र

कुसमी तहसील सीधी जिले की छह तहसीलों में से एक है, जो जिले के दक्षिण-पूर्वी भाग में, छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा के निकट स्थित है। भौगोलिक दृष्टि से यह तहसील सघन वन-क्षेत्र, पहाड़ी भू-भाग तथा बिखरी हुई ग्राम-बसाहट से

चिन्हित है, जो इसे जिले की अपेक्षाकृत अधिक दुर्गम तहसीलों में सम्मिलित करती है। द्वितीयक स्रोतों (जनगणना 2011; मध्य प्रदेश जनजातीय अनुसंधान एवं विकास संस्थान, भोपाल) के अनुसार कुसमी तहसील में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का अनुपात जिले के औसत से भी अधिक है, जिसमें बैगा (एक विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के रूप में वर्गीकृत), कोल तथा गोंड जनजातियों की प्रमुख उपस्थिति है।

आर्थिक दृष्टि से तहसील की अर्थव्यवस्था मूलतः निर्वाह-कृषि, वनोपज-संग्रहण (जैसे तेंदूपत्ता, महुआ) तथा पशुपालन पर आधारित है। अवसंरचनात्मक दृष्टि से, सड़क-सम्पर्क, विद्युतीकरण तथा दूरसंचार-नेटवर्क का विस्तार जिले के अन्य, अपेक्षाकृत सुगम्य तहसीलों (जैसे सीधी, सिहावल) की तुलना में धीमा रहा है, यद्यपि विगत एक दशक में इसमें क्रमिक सुधार दर्ज किया गया है। साक्षरता-दर, विशेषतः महिला-साक्षरता, तहसील में राज्य तथा राष्ट्रीय औसत से उल्लेखनीय रूप से पीछे है। यह संयुक्त भौगोलिक, आर्थिक तथा सामाजिक पृष्ठभूमि कुसमी तहसील को ग्रामीण विकास तथा जनसंचार माध्यमों के अन्तर्सम्बन्ध के अध्ययन हेतु एक विशेष रूप से सार्थक तथा आवश्यक क्षेत्र बनाती है।

ग्रामीण विकास और जनसंचार माध्यमों की भूमिका

समाजशास्त्रीय दृष्टि से जनसंचार माध्यमों को ग्रामीण विकास के एक महत्वपूर्ण अभिकरण के रूप में स्वीकार किया गया है। डेनियल लर्नर (1958) के आधुनिकीकरण सिद्धांत से लेकर एवरेट रोजर्स (2003) के नवाचार-प्रसार सिद्धांत तक, यह सुस्थापित है कि जनसंचार माध्यम ग्रामीण जनसंख्या में जागरूकता उत्पन्न करने तथा नवीन विचारों, तकनीकों एवं सरकारी योजनाओं के प्रसार में एक केन्द्रीय भूमिका निभाते हैं। भारत में इसरो द्वारा संचालित "उपग्रह अनुदेशात्मक दूरदर्शन प्रयोग" (SITE, 1975-76) से लेकर वर्तमान डिजिटल इंडिया पहल तक, यह मान्यता निरन्तर सुदृढ़ होती गई है कि जनसंचार माध्यमों के बिना ग्रामीण विकास की गति तथा पहुँच, दोनों सीमित रह जाती हैं।

प्रस्तुत अध्ययन में कुसमी तहसील की 100 ग्रामीण महिलाओं के घर में जनसंचार साधनों की उपलब्धता का विवरण तालिका 1 में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 1 : उत्तरदाताओं के घर में जनसंचार साधनों की उपलब्धता (N=100, बहु-उत्तर)

क्र.	साधन	उपलब्ध (संख्या)	प्रतिशत
1	रेडियो	18	18.0
2	दूरदर्शन (टीवी)	50	50.0
3	मोबाइल फोन	82	82.0
4	स्मार्टफोन/इंटरनेट-सुविधा सहित	35	35.0
5	समाचार-पत्र (नियमित)	12	12.0

स्रोत: क्षेत्र-सर्वेक्षण, 2025 /

तालिका 1 से स्पष्ट होता है कि मोबाइल फोन (82.0 प्रतिशत) कुसमी तहसील में सर्वाधिक व्यापक जनसंचार साधन है, तत्पश्चात् दूरदर्शन (50.0 प्रतिशत) का स्थान है। यह उल्लेखनीय है कि ये आँकड़े जिले के अन्य, अधिक सुगम्य तहसीलों की तुलना में कुछ निम्न हैं, जो कुसमी की भौगोलिक दुर्गमता तथा अपेक्षाकृत विलम्बित अवसंरचनात्मक विकास को प्रतिबिम्बित करते हैं। समाचार-पत्र की उपस्थिति सबसे सीमित (12.0 प्रतिशत) पाई गई, जो निम्न साक्षरता-दर के प्रत्यक्ष अनुरूप है।

ग्रामीण विकास से सम्बन्धित जानकारी के स्रोतों को अधिक विशिष्ट रूप से समझने हेतु उत्तरदाताओं से यह पूछा गया कि उन्हें सरकारी योजनाओं, कृषि-सम्बन्धी नवाचार तथा स्वास्थ्य-सम्बन्धी सूचना मुख्यतः किस स्रोत से प्राप्त होती है, जिसका विवरण तालिका 2 में प्रस्तुत है।

तालिका 2 : ग्रामीण विकास योजनाओं की जानकारी का प्रमुख स्रोत (N=100)

क्र.	सूचना-स्रोत	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1	जनसंचार माध्यम (रेडियो/दूरदर्शन/मोबाइल)	42	42.0
2	सरकारी कर्मचारी (पटवारी/आँगनवाड़ी कार्यकर्ता आदि)	25	25.0
3	पड़ोसी/परिवार के सदस्य	20	20.0

क्र.	सूचना-स्रोत	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
4	ग्राम सभा/पंचायत बैठक	8	8.0
5	अन्य	5	5.0
	योग	100	100.0

स्रोत: क्षेत्र सर्वेक्षण, 2025।

तालिका 2 का निष्कर्ष विशेष रूप से महत्वपूर्ण है: जनसंचार माध्यम (42.0 प्रतिशत) ग्रामीण विकास योजनाओं की जानकारी का सर्वाधिक सामान्य स्रोत बनकर उभरे हैं, जो सरकारी कर्मचारियों (25.0 प्रतिशत) तथा पारम्परिक अन्तर्व्यक्तिक स्रोतों (पड़ोसी/परिवार, 20.0 प्रतिशत) से भी आगे हैं। यह निष्कर्ष इस बात की पुष्टि करता है कि परम्परागत "ऊपर से नीचे" प्रशासनिक सूचना-प्रसार तंत्र (जैसे पटवारी, ग्राम सभा) की तुलना में जनसंचार माध्यम अब कुसमी जैसी दुर्गम तहसील में भी सूचना-प्रसार का एक अधिक प्रभावी तथा सुगम माध्यम बनते जा रहे हैं। ग्राम सभा/पंचायत बैठक का अपेक्षाकृत सीमित योगदान (8.0 प्रतिशत) भी उल्लेखनीय है, जो पंचायती राज संस्थाओं की सूचना-प्रसार क्षमता में सुधार की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

माध्यम-उपयोग की तीव्रता तथा ग्रामीण विकास योजनाओं की जागरूकता के मध्य सम्बन्ध को अधिक स्पष्ट रूप से समझने हेतु उत्तरदाताओं को उनके समेकित माध्यम-उपयोग सूचकांक (उच्च/मध्यम/निम्न) के आधार पर वर्गीकृत करते हुए, इसका सम्बन्ध उनकी ग्रामीण विकास योजनाओं (जैसे मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन) की जागरूकता-स्तर से स्थापित किया गया, जिसका विवरण तालिका 3 में प्रस्तुत है।

तालिका 3 : माध्यम-उपयोग स्तर एवं ग्रामीण विकास योजनाओं की जागरूकता का क्रॉस-सारणीयन (N=100)

माध्यम-उपयोग स्तर	उच्च जागरूकता	मध्यम जागरूकता	निम्न जागरूकता	योग
उच्च (35)	20	12	3	35
मध्यम (33)	8	18	7	33
निम्न (32)	3	10	19	32
योग	31	40	29	100

स्रोत: क्षेत्र-सर्वेक्षण, 2025 /

तालिका 3 से एक स्पष्ट तथा सुसंगत प्रवृत्ति उभरती है : उच्च माध्यम-उपयोग वाली 35 महिलाओं में से 20 (57.1 प्रतिशत) उच्च जागरूकता-स्तर रखती हैं, जबकि निम्न माध्यम-उपयोग वाली 32 महिलाओं में से केवल 3 (9.4 प्रतिशत) ही उच्च जागरूकता-स्तर रखती हैं। इसके विपरीत, निम्न-उपयोग समूह में निम्न जागरूकता की दर 59.4 प्रतिशत है, जबकि उच्च-उपयोग समूह में यह दर घटकर मात्र 8.6 प्रतिशत रह जाती है। यह प्रबल, दिशात्मक सम्बन्ध इस निष्कर्ष की पुष्टि करता है कि जनसंचार माध्यमों का उपयोग कुसमी तहसील में भी, अन्य अपेक्षाकृत सुगम्य क्षेत्रों की भाँति, ग्रामीण विकास-सम्बन्धी जागरूकता का एक सशक्त निर्धारक है।

तथापि यह भी उल्लेखनीय है कि जागरूकता तथा वास्तविक योजना-लाभ के मध्य एक सम्भावित अन्तराल विद्यमान हो सकता है, जिसे रॉबर्ट हॉर्निक (1988) ने अपने अध्ययन में विकासशील देशों के व्यापक अनुभव के आधार पर रेखांकित किया है-केवल जागरूकता उत्पन्न करना पर्याप्त नहीं, अपितु इसे वास्तविक लाभ में परिणत करने हेतु सुगम प्रशासनिक प्रक्रिया तथा पूरक संस्थागत सहयोग भी आवश्यक है। कुसमी तहसील के सन्दर्भ में, दुर्गम भौगोलिक अवस्थिति तथा सीमित प्रशासनिक उपस्थिति के कारण यह अन्तराल विशेष रूप से प्रासंगिक प्रतीत होता है, तथा भावी अध्ययनों में इसका प्रत्यक्ष परीक्षण किया जाना चाहिए।

द्वितीयक स्रोतों से प्राप्त जिला-स्तरीय आँकड़ों के साथ तुलना करने पर भी यह स्पष्ट होता है कि कुसमी तहसील की स्थिति सीधी जिले के समग्र औसत से पीछे है-यह अन्तर तहसील की भौगोलिक दुर्गमता, उच्च जनजातीय जनसंख्या-अनुपात तथा विलम्बित अवसंरचनात्मक विकास का संयुक्त परिणाम प्रतीत होता है, जो कुसमी को जिले के भीतर एक विशेष, लक्षित नीतिगत ध्यान की माँग करने वाले उप-क्षेत्र के रूप में चिन्हित करता है।

निष्कर्ष

प्रस्तुत अध्ययन के प्रमुख निष्कर्ष निम्नानुसार संक्षेपित किए जा सकते हैं :

1. कुसमी तहसील की ग्रामीण महिलाओं में मोबाइल फोन (82.0 प्रतिशत) सर्वाधिक व्यापक जनसंचार साधन है, तत्पश्चात् दूरदर्शन (50.0 प्रतिशत) का स्थान है, जबकि रेडियो तथा समाचार-पत्र की उपस्थिति अपेक्षाकृत सीमित है।

2. जनसंचार माध्यम (42.0 प्रतिशत) ग्रामीण विकास योजनाओं की जानकारी का सर्वाधिक सामान्य स्रोत हैं, जो परम्परागत प्रशासनिक तथा अन्तर्व्यक्तिक सूचना-स्रोतों से भी आगे निकल चुके हैं।
3. माध्यम-उपयोग स्तर तथा ग्रामीण विकास योजनाओं की जागरूकता के मध्य सांख्यिकीय रूप से सार्थक, प्रबल सकारात्मक सम्बन्ध पाया गया।
4. कुसमी तहसील की भौगोलिक दुर्गमता, उच्च जनजातीय जनसंख्या-अनुपात तथा विलम्बित अवसंरचनात्मक विकास इसे जिले के अन्य तहसीलों की तुलना में जनसंचार-पहुँच तथा ग्रामीण विकास, दोनों दृष्टि से पीछे रखते हैं।
5. जागरूकता तथा वास्तविक योजना-लाभ के मध्य एक सम्भावित अन्तराल विद्यमान प्रतीत होता है, जो केवल सूचना-प्रसार के स्थान पर सुगम प्रशासनिक कार्यान्वयन की भी आवश्यकता को रेखांकित करता है।

सुझाव

प्रस्तुत अध्ययन के निष्कर्षों के आधार पर निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत किए जाते हैं :

1. कुसमी जैसी दुर्गम तहसीलों में मोबाइल तथा दूरदर्शन नेटवर्क के विस्तार को विशेष प्राथमिकता दी जानी चाहिए, जिससे भौगोलिक दुर्गमता से उत्पन्न सूचना-अन्तराल को कम किया जा सके।
2. ग्रामीण विकास योजनाओं के प्रचार-प्रसार में जनसंचार माध्यमों (विशेषतः मोबाइल-आधारित संक्षिप्त सन्देश तथा स्थानीय भाषा में दूरदर्शन/रेडियो कार्यक्रम) के उपयोग को सुदृढ़ किया जाना चाहिए।
3. पंचायती राज संस्थाओं (ग्राम सभा) की सूचना-प्रसार क्षमता को सुदृढ़ करने हेतु उन्हें जनसंचार माध्यमों के साथ समन्वित करते हुए एक "मिश्रित सम्प्रेषण रणनीति" अपनाई जानी चाहिए।
4. जागरूकता तथा वास्तविक लाभ के मध्य अन्तराल को कम करने हेतु सूचना-प्रसार के साथ-साथ आवेदन-प्रक्रिया के सरलीकरण तथा ग्राम-स्तरीय सहायता-केन्द्रों की स्थापना पर भी समान बल दिया जाना चाहिए।
5. आँगनवाड़ी तथा आशा कार्यकर्ताओं को डिजिटल/जनसंचार साक्षरता का प्रशिक्षण देकर उन्हें ग्राम-स्तर पर सूचना-प्रसार के औपचारिक मध्यस्थ के रूप में सुदृढ़ किया जाना चाहिए।

संदर्भ सूची

1. कोठारी, सी.आर. (2004). अनुसंधान प्रविधि : विधियाँ एवं तकनीकें. नई दिल्ली : न्यू एज इंटरनेशनल पब्लिशर्स।
2. कुमार, केवल जे. (2010). भारत में जनसंचार माध्यम (4था संस्करण). मुम्बई : जायको पब्लिशिंग हाउस।
3. भारत की जनगणना, 2011. प्राथमिक जनगणना सार, मध्य प्रदेश, सीधी जिला। नई दिल्ली : भारत सरकार।
4. मध्य प्रदेश शासन. मध्य प्रदेश मानव विकास प्रतिवेदन. भोपाल : राज्य योजना आयोग (विभिन्न वर्ष)।
5. मध्य प्रदेश जनजातीय अनुसंधान एवं विकास संस्थान, भोपाल. मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों का सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण (विभिन्न वर्ष)।
6. जिला सांख्यिकी पुस्तिका, सीधी (विभिन्न वर्ष). भोपाल : अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, मध्य प्रदेश शासन।
7. Hornik, R. C. (1988). Development Communication: Information, Agriculture, and Nutrition in the Third World. New York: Longman.
8. Lerner, D. (1958). The Passing of Traditional Society: Modernizing the Middle East. Glencoe: Free Press.
9. Rogers, E. M. (2003). Diffusion of Innovations (5th ed.). New York: Free Press.
10. Schramm, W. (1964). Mass Media and National Development: The Role of Information in the Developing Countries. Stanford: Stanford University Press.
11. Melkote, S. R., & Steeves, H. L. (2001). Communication for Development in the Third World: Theory and Practice for Empowerment. New Delhi: Sage Publications.
12. Indian Space Research Organisation. (1977). SITE: Satellite Instructional Television Experiment — Evaluation Report. Ahmedabad-New Delhi: ISRO/Planning Commission.

13. Kabeer, N. (1999). Resources, agency, achievements: Reflections on the measurement of women's empowerment. *Development and Change*, 30(3), 435-464.

